been observed, particularly in the border areas of Gujarat and Rajasthan which provide easy routes for smuggling of narcotics and cross-sbusidised flow of weapons from across the border.

Government have initiated several steps to check the smuggling of arms and other contraband items, which include strengthening of paramilitary force deployment, intensified patrolling and use of sophisticated "border surveillance equipments.

The issue of Pakistan's support to terrorism in India has been taken up by Government at different interna-
anal levels and the responses have
rn encouraging.

मानवाधिकार आयोग

299. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक मानवाधिकार आयोग गठित किये जाने के संबंध में विभिन्न दलों के साथ विचार विमर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त मानवाधिकार आयोग की स्थापना करने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ग) एक मानवाधिकार आयोग के गठन सहित मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए दिनांक 14.9.1992 को मानवाधिकारों पर मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन ने मानवाधिकार आयोग के गठन का स्वागत किया और सुझाव दिया कि सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रियों तथा पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक समिति, इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित कानून की जांच करने हेतु गठित की जाए।

तदनुसार इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय समिति गठित की गई। इस समिति की दिनांक 12.10.92 को बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि देश के विभिन्न भागों में सेमिनार आयोजित करके समाज के विभिन्न वर्गों के विचार जाने जाएं। ऐसे चार सेमिनार बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा हैदराबाद में आयोजित किए गए एक सेमिनार दिल्ली में भी, भारतीय बार काउंसिल द्वारा आयोजित किया गया था। दिनांक 28 जनवरी, 1993 को इस विषय पर विचार करने के लिए गृह सचिव ने बड़े राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों की एक बैठक बुलाई। केन्द्रीय गृह मंत्री ने भी इस मामले पर संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ दिनांक 8.2.1993 को विचार-विमर्श किया। इस विचार-विमर्श के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 18 फरवरी, 1993 को एक और बैठक हुई।

इन सभी विचार-विमर्शों में इस बात पर आम सहमति थी कि एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इन विचार-विमर्शों में तथा समिति के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए मतों को ध्यान में रखते हुए आयोग के गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए अब कार्रवाई की जा रही है। संसद के चालू सत्र के दौरान आयोग के गठन के लिए एक विधेयक पेश किए जाने की आशा है।

Riots in Bombay

299. SHRI SURESH KALMADI
SHRI KAMAL MORARKA:
SHRI GAYA STNGH:
SHRI CHATURANAN MISHRA;

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fresh Communal riots broke out in Bombay in the first week of January, 1993;

(b) *if*so, what are the repercussions of these riots; how many people were killed; estimated loss of property and what is the estimated number of non-Maharashtrfan residents of Bombay fled from the city following the riots;

(c) whether it is a fact that Aytu dhya incidents has no direct bearing over these fresh riots;

(d) if so, whether any inquiry has been conducted into the reasons for these riots; if so, th$_e$ details and outcome thereof;

(e) steps taken to normalise the situation; and

(f) precautionery and remedial measures taken to prevent the recurrence of such riots in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) Yes, Sir.

(b) According *to* informaion furnished by State Government 555 persons were killed in January, 1993 riots. No estimates are available. Information about th$_e$ l°ss of property is not maintained by Central Govern-ment.

(c) and (d) A judicial inquiry will be conducted by Shri Justice B. N. Shrikrishna a sitting Judge of the Bombay High Court.

(e) To coordinate the work of relief and rehabilitation for normalising the situation an apex committee under the chairmanship of th$_e$ Governor of Maharashtra has been constituted. The apex committee has identified among other things, the need to en sure adequate measures for return of the riot victims *to* their residential areas, countering rumour mongering and using the media for spreading the message of peace & harmony.

(f) The primary responsibility for the maintenance of law and order rests with the State which take ap propriate remedial and preventive measures from, time to time.

Persons billed in Injured in recent Communal riots

300. SHRI S. K. T. RAMACHAND-RAN; WiU .the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of deaths due to communal riots in the country in the wake of Babri Mas] id demolition;

(fo) haw may were injured in these riots;

(c) whether Government will ban Shiv Sena, which owned the responsibility for *the* communal riots in Bombay;

(d) whether Government have found out the organisations responsible for the bomb blasts in Tamilnadu
on the eve of Republic Day 26th January, 1993; and

(e) whether any foreign territorist forces are behind the violence in Tamilnadu and Bombay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI! P. M. SAYEED): (a) and (b) 1940 killed; 6109 injured.

(c) Government will have to study various aspects of the matter before any decision in the matter can be taken.

(d) and (e) -Information is being collected.

प्रतिबंधित संगठनों स संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी

301. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित कितने व्यक्तियों को 15 फरवरी, 1993 तक उत्तर प्रदेश मध्य देश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तार किया गया ; और